

सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-31 अंक-19 7 अक्टूबर, 2016

मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

कुल पृष्ठ 8

मूल्य : 2 रुपये

उड़ी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले की निंदा

29 सितम्बर, 2016 को एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने कोलकाता में प्रेस को जारी एक बयान में कहा :

“उड़ी में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला निन्दनीय है लेकिन भारत सरकार द्वारा प्रतिकार में उठाए गए कदमों से समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि इससे दोनों देशों के बीच युद्ध तनाव बढ़ेगा जो आम लोगों के हितों के सर्वथा विपरीत है। जिस चीज को तुरंत जरूरत है वह है दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत ताकि आतंकवाद पर काबू पाया जा सके।

राशन में मिट्टी तेल के कोटे में कटौती के जनविरोधी फैसले को तुरंत वापस लेने की एसयूसीआई(सी) ने की जोरदार मांग

29 सितम्बर, 2016 को एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने कोलकाता में प्रेस को जारी एक बयान में कहा :

बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार ने राशन में मिट्टी तेल के कोटे में औसतन 25 प्रतिशत की कटौती कर दी है। असम, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में यह कटौती 36 प्रतिशत तक है। पश्चिम बंगाल में 80 किलोलीटर से घटाकर 58.688 किलोलीटर यानी 17.3 प्रतिशत (12.276 किलोलीटर) की कटौती 1 अक्टूबर 2016 से कर दी गई है। केन्द्रीय सरकार ने मिट्टी तेल में दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती का फैसला लिया है और तेल कम्पनियों को सलाह दी है कि खुले बाजार में मिट्टी तेल की बिक्री को बढ़ायें। इस तरह सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बजाय आवश्यक वस्तुओं के वितरण को निजी ऑपरेटरों के हवाले कर रही है।

हमारा दृढ़ मत है कि इस कदम से पूंजीपतियों और तेल कम्पनियों के मालिकों को छूट मिल जाएगी लोगों को और भी निचोड़ने की तथा उन पर आर्थिक हमले तेज करने की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राशन व्यवस्था में 16 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले खुले बाजार में एक लीटर मिट्टी तेल के दाम 50 रुपये या उससे भी ज्यादा हैं।

हम इस जनविरोधी फैसले को तुरंत वापस लेने और मिट्टी तेल सहित सभी आवश्यक चीजों के मदों में सब्सिडी बढ़ाने की केन्द्र सरकार से जोरदार मांग करते हैं। हम लोगों से भी आह्वान करते हैं कि केन्द्र सरकार के इस फैसले को वापस कराने के लिए एक जोरदार जनआन्दोलन खड़ा करें।

चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड को बंद करने के केन्द्र सरकार के फैसले की भी हम कड़ी निंदा करते हैं।

हजारीबाग हत्याकाण्ड की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग

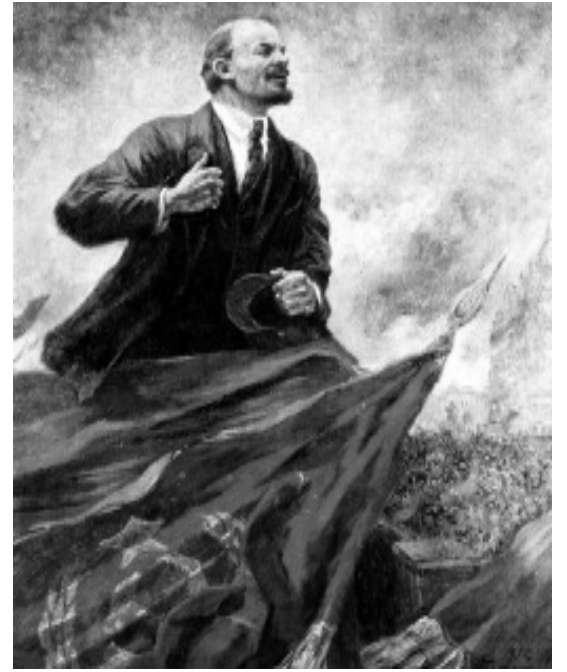
ऑल इण्डिया कृषक खेजमजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) की ओर से कॉमरेड सत्यवान ने 2 अक्टूबर को प्रेस को जारी एक बयान में कहा : झारखण्ड में हजारीबाग जिला के बड़का गांव में 1 अक्टूबर को पुलिस द्वारा किसानों और आदिवासियों

(शेष पृष्ठ 2 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति की यादगार सीख और सार्थकता

(1917 में हुई रूस की नवम्बर क्रान्ति की 100वीं वर्षगांठ पर सर्वहारा दृष्टिकोण के वर्ष 26 अंक 20-21 में छपे इस लेख को पुनःप्रकाशित कर रहे हैं।)

दुनिया के तमाम देशों में पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के निर्मम शोषण से त्रस्त मेहनतकश अवाम की मुक्ति की जो महती ऐतिहासिक जिम्मेवारी इतिहास ने इस युग के सच्चे कम्युनिस्टों के कंधों पर सौंपी है, हर साल नवम्बर क्रान्ति दिवस हमें उस जिम्मेवारी की याद दिला देता है। दुनिया भर के कम्युनिस्टों के लिए यह खास दिवस मनाया महज रस्म अदायगी नहीं है। यह दिन आने वाले दिनों के क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत से अतीत के क्रांतिकारी आंदोलन के तजुर्बों की गहन समीक्षा कर उससे सीख लेने का दिन है। 1917 की महान नवम्बर क्रान्ति, जिसने विश्व पूंजीवाद के चक्रव्यूह को तोड़कर रूस में दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की थी, एक युगांतकारी घटना थी। लेकिन यह घटना अचानक नहीं घटी थी। क्रांतिकारी सिद्धांत को वास्तव में किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है, उसी की एक जीती-जागती मिसाल है नवम्बर क्रान्ति। मानव-समाज की प्रगति को बाधित करने वाली शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था की जंजीरों को तोड़कर इस क्रान्ति ने हर मामले में पिछड़े हुए रूस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। विभिन्न देशों में



सर्वहारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें महान नवम्बर क्रान्ति से सीख लेनी ही होगी।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

शिक्षा की ज्वलंत मांगों पर छात्रों का संसद मार्च

दिल्ली : आठवीं कक्षा तक पास-फेल प्रणाली पुनः चालू करने व 5वीं और 8वीं के बोर्ड पुनः बहाल करने, शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, केन्द्रीकरण व साम्प्रदायीकरण बंद करने, आदि शिक्षा क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन (एआईडीएसओ) ने 27 सितम्बर को अखिल भारतीय छात्र रैली आयोजित की रैली रामलीला मैदान के पास गुरु नानक आई हॉस्पिटल से शुरू हुई और संसद मार्ग की ओर आगे बढ़ी। देश के 23 राज्यों से हजारों छात्रों ने रैली में जोश-खरोश के साथ शिरकत की।

संसद मार्ग पर पुलिस द्वारा जुलूस रोक दिये जाने

पर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा, एआईडीएसओ की अखिल भारतीय कमेटी के उपाध्यक्षों कॉमरेड मुकेश सेमवाल, भास्करानंद, भाविक राजा, अंशुमान राय और विभिन्न राज्यों के नेताओं ने सम्बोधित किया।

सभा की अध्यक्षता एआईडीएसओ के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. कमल साई ने की।

एआईडीएसओ के उपाध्यक्ष कॉमरेड राजशेखर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ज्वाइंट सिक्रेटरी के जरिये केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा।



महान नवम्बर क्रांति...

(पृष्ठ 1 का शेष)



महान क्रांतिकारी दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने ही सबसे पहले समाज-विकास के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर पूँजीवादी व्यवस्था के खात्मे और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के अवश्यम्भावी होने का एलान किया था। उन्होंने ही सबसे पहले दिखाया था कि सर्वहारा वर्ग को लामबंद कर पूँजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष में उतरने की जमीन खुद बुर्जुआ समाज ही तैयार कर देता है और इसलिए दो परस्पर विरोधी वर्गों के बीच जारी वर्ग-संघर्ष के तेज होने से सामाजिक क्रांति के जरिये पहले समाजवाद और बाद में साम्यवाद की ओर मानव-समाज अनिवार्य रूप से अग्रसर होता है। जब तक अनियंत्रित उत्पादन व्यवस्था और वस्तुजगत व भावजगत में व्यक्तिगत मालिकाना मौजूद रहेगा, तब तक यह वर्ग-संघर्ष जारी रहेगा। पूँजीवादी समाज के विकास के साथ-साथ सर्वहारा वर्ग के आविर्भाव की घटना को समाज के 'कोढ़' के रूप में न देख कर मार्क्स ने ही सबसे पहले कहा था कि इसके चलते समाज अपने मुख्य द्वन्द्व से मुक्त होगा। समाज-विकास की इस धारा को चिह्नित कर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नामक अपने दर्शन में उन्होंने दिखाया कि यह परिवर्तन कोई कपोल कल्पना नहीं है, इसका आधार विज्ञान है। दुनिया के सर्वहारा वर्ग को भी मार्क्सवादी दर्शन में पूँजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष का एक ताकतवर हथियार मिला था। धीरे-धीरे कार्ल मार्क्स की सीख सारी दुनिया में फैल गयी और इसने मजदूर वर्ग के अंदर चेतना पैदा की। सन् 1864 में कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन

हजारीबाग हत्याकांड...

(पृष्ठ 1 का शेष)

की क्रूरता से की गई हत्याओं की ऑल इण्डिया कृषक खेजमजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) कड़ी निंदा करता है। वे लोग बिना मुआवजा दिये और बिना पुनर्वासन के नाजायज शर्तों पर उनकी जमीनों को जबरन हड़पे जाने के लिए कठिन और कठोर संघर्ष कर रहे थे। झारखण्ड सरकार और राज्य प्रशासन प्राकृतिक न्याय की न्यूनतम रीति-नीतियों तक की पालना न करते हुए, यहां तक कि पीड़ितों से किये गए वादों को तोड़ते हुए दमन-उत्पीड़न के एजेण्ट के रूप में काम कर रहा है। एआईकेकेएमएस मांग करता है कि इस हत्याकाण्ड की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाये, पुलिस को वहां से हटाया जाये और हर तरह की दमनात्मक कार्रवाइयों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इस हत्याकाण्ड के लिए जिम्मेदार सभी पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। हर मृतक के परिवार को कम से कम 20 लाख रुपये मुआवजा देने और घायलों का पूरा इलाज कराने की भी सरकार से मांग की गई। प्रभावित क्षेत्रों में उक्त जमीन का अधिग्रहण तुरंत बंद किया जाये। मृतकों के शोकसंतपत परिवार के प्रति हम शोक संवेदना और सरोकार व्यक्त करते हैं। हम सभी तबकों के लोगों से अपील करते हैं कि झारखण्ड की बीजेपी सरकार की इस भयावह करतूत की निंदा करने के लिए आगे आयें।

'इंटरनेशनल वर्किंग मेन्स एसोसिएशन' का जन्म हुआ।
क्रांति के पहले का रूस

इस बीच निरंकुश जारशाही के जमाने में रूस में पूँजीवाद का धीरे-धीरे विकास हो रहा था। मार्क्स की सीख धीरे-धीरे वहाँ भी पहुँची। लेनिन के अनुसार "मार्क्स-एंगेल्स को रूसी भाषा की बखूबी जानकारी थी, वे रूसी किताबें भी पढ़ते थे। रूस के बारे में उन्हें काफी दिलचस्पी थी और वहाँ के क्रांतिकारियों के साथ उनका रिश्ता भी था।" (वॉल्यूम 2 पेज-19) मार्क्सवादियों के आगमन के पहले तक रूस के जार-विरोधी आंदोलन में मुख्यतः नरोदनिकवाद का ही प्रभाव व्याप्त था। नरोदनिकवादी जारशाही का खात्मा तो चाहते थे लेकिन उनका मानना था कि यह काम दशदशत पैदा कर व्यक्तियों की हत्या से ही संभव है। नरोदनिकवादियों का मानना था कि जारशाही के खात्मे के लिए कुछ जांबाज लोगों की सक्रिय वीरतापूर्ण भूमिका ही काफी है। इसमें आम जनता की कोई खास भूमिका नहीं है। महान स्तालिन के मुताबिक नरोदनिक सिद्धांत का आधार था 'Active heroes and passive mobs' यानी हीरो चुस्त और लोगों की भीड़ सुस्त। क्रांति में मजदूर वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका और उसके लिए उसकी अपनी क्रांतिकारी पार्टी की जरूरत को नरोदनिकवादी नकारते थे। इसलिए उनका सिद्धांत क्रांति का विरोधी था। रूस में मार्क्सवाद के सम्पर्क में सबसे पहले प्लेखानोव आये थे और वहाँ वे एक असाधारण प्रचारक के रूप में उभरे थे। हालांकि, वे अपने शुरूआती जीवन में नरोदनिकवाद में विश्वास करते थे। मार्क्स-एंगेल्स की प्रसिद्ध पुस्तक 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' का उनकी लिखी भूमिकाओं सहित उन्होंने रूसी भाषा में अनुवाद किया। मार्क्स-एंगेल्स की काफी रचनाओं का रूसी में अनुवाद हुआ। 1883 में रूस में प्लेखानोव ने ही सबसे पहले 'मजदूर-मुक्ति' ('Emancipation of Labour') नामक एक मार्क्सवादी गुप की स्थापना की थी। इस गुप ने नरोदनिकवाद के पैरोकारों के गलत सिद्धांतों के खिलाफ वैचारिक संघर्ष चलाकर मार्क्सवाद के पक्ष में पूरे देश में प्रचार किया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर नरोदनिक सिद्धांत के खिलाफ वैचारिक संघर्ष चलाकर प्लेखानोव ने कुछ निबंध लिखे। इनमें खास तौर पर उल्लेखनीय है इतिहास के अद्वैतवादी दृष्टिकोण के विकास के बारे में' (On the development of the monistic view of history)। लेनिन के अनुसार इस निबंध ने 'रूस में मार्क्सवादियों की पूरी एक पीढ़ी को शिक्षित किया था'। यह सही है कि नरोदनिकवाद का खण्डन करके मार्क्सवाद आगे बढ़ा, लेकिन प्लेखानोव ने कुछ गंभीर गलतियाँ की थी। नरोदनिक दर्शन के खिलाफ कठोर संघर्ष छेड़ने के बावजूद उसका कुछ असर उनके चिन्तन में रह गया था। व्यक्ति-हत्या की राजनीति में उनका विश्वास था। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में क्रांति में किसान समुदाय की सहयोगी भूमिका के बारे में उनका नजरिया साफ नहीं था। उनका सोचना था कि उदारवादी बुर्जुआ वर्ग मजदूरों के हितों की हिफाजत में मदद करता है। सर्वोपरि, तत्कालीन दूसरे मार्क्सवादी गुपों की तरह उनके संगठन 'मजदूर-मुक्ति' ('Emancipation of Labour') का भी मजदूर आंदोलन के बारे में कोई वास्तविक अनुभव नहीं था।

प्लेखानोव की कमियों को दूर कर मार्क्सवाद के आधार पर मजदूर वर्ग के आंदोलन को निर्मित करने की जिम्मेवारी लेनिन पर आ पड़ी। क्रांतिकारी छात्र आंदोलन में शिरकत करने के 'जुर्म' में महज 18 साल की उम्र में ही लेनिन को काजान विश्वविद्यालय से निष्कासित कर पुलिस की हिरासत में ले लिया गया था। उस दौरान वे फेदोसेव द्वारा स्थापित एक मार्क्सवादी गुप में शामिल हुए। बाद में समारा में जाकर उन्होंने स्वयं एक मार्क्सवादी गुप की स्थापना की। 1893 में वे सेंट पीटर्सबर्ग चले गये। इसके बाद 1895 में उन्होंने सारे मार्क्सवादी गुपों को एकत्रित कर 'लीग ऑफ स्ट्रगल फोर द वर्किंग क्लास' (मजदूर वर्ग के मुक्ति-संघर्ष के लिए लीग) का गठन किया और मजदूरों को लेकर एक के बाद एक आंदोलन संगठित करना शुरू किया। लेनिन ही सबसे पहले उस देश में मजदूर आंदोलन में वैज्ञानिक समाजवाद की सीख लाये। रूस में उस समय भी नरोदनिकवाद का प्रभाव था और लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध

पुस्तक 'जनता के मित्र कौन हैं और सोशल डेमोक्रेटों से वे कैसे लड़ते हैं' ('What the friends of the people are and how they fight the social democrats') में इस सिद्धांत की गलतियों को उजागर किया। उस दौरान रूस में प्लेखानोव के गुप सहित तमाम मार्क्सवादी गुपों को एकजुट कर मजदूरों की एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी निर्मित करने की कोशिश हो रही थी। (उस दौरान सोशल डेमोक्रेसी का अवसरवादी और समझौतापरस्त चरित्र साफ तौर पर उजागर नहीं हुआ था और इसलिए कम्युनिस्ट आंदोलन से सोशल डेमोक्रेटों को हटाया नहीं गया था) ठीक उसी समय 1897 में लेनिन की गिरफ्तारी हुई। उनको साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। वहाँ रहकर भी लेनिन ने गुप्त रूप से कॉमरेडों के साथ सम्पर्क बनाये रखा और इस दौरान कुछ लेख भी लिखे। उस दौरान रूस के मजदूर आंदोलनों में अर्थवाद का रुझान काम कर रहा था। इसलिए मजदूर राजनैतिक-सैद्धांतिक चर्चा और पार्टी निर्माण की प्रक्रिया को छोड़कर महज आर्थिक मांगों को हासिल करने में ही व्यस्त थे। साइबेरिया में निर्वासन के दौरान लेनिन ने इस रुझान के खिलाफ काफी लेख लिखे।

ईस्क्रा का प्रकाशन

लेनिन की 'लीग ऑफ स्ट्रगल फोर द वर्किंग क्लास' सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी की बुनियाद थी। रूस के विभिन्न शहरों में लीग की शाखाएँ बन रही थीं। इसका लक्ष्य था रूस में सर्वहारा वर्ग की एक एकताबद्ध पार्टी की स्थापना करना।

1898 के मार्च में पुलिस की नजर बचाकर अच्छी तादाद में सोशल डेमोक्रेटिक संगठनों के प्रतिनिधि मिंस्क शहर में एकत्रित हुए। वहाँ 'रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी' ('आरएसडीएलपी') की स्थापना करने की घोषणा हुई। हालांकि, उस समय पार्टी की स्थापना नहीं की जा सकी। लेनिन निर्वासित थे। उनकी गैरमौजूदगी में संगठन के काम-काज में दिक्कतें आ रही थीं। बहुत जल्द ही पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य भी पुलिस की गिरफ्त में आ गये। दूसरे सोशल डेमोक्रेटिक संगठन अलग-अलग तरीके से अपने-अपने ढंग से काम करते रहे।



निर्वासन के दौरान लेनिन ने सारे सोशल डेमोक्रेटिक संगठनों को एकजुट कर पार्टी निर्माण की विस्तृत योजना तैयार की। उस दौरान उन्होंने एक ऐसे राजनैतिक पत्र के प्रकाशन की जरूरत महसूस की, जो पूरे रूस में फैले तमाम मार्क्सवादी गुपों और संगठनों के बीच सम्पर्क कायम करे और पार्टी निर्माण का पथ प्रशस्त करे।

लेनिन ने निर्वासन से लौटने के बाद दिसम्बर 1900 में प्लेखानोव के साथ मिलकर 'ईस्क्रा' (चिंगारी) अखबार का पहला अंक प्रकाशित किया। उसके पहले पन्ने पर लिखा था 'चिंगारी ज्वाला भड़का देगी।' 'ईस्क्रा' देश के बाहर छपता था और प्रशासन की नजर बचाकर गुप्त रूप से रूस लाया जाता था। अखबार बाँटने के दौरान अगर कोई पकड़ा जाता, तो जार के सख्त निर्देश पर उसे जेल या निर्वासन की सजा होना तय था। लेकिन इतनी रुकावटों के बावजूद 'ईस्क्रा' के प्रचार को रोका नहीं जा सका। पूरे रूस में यह अखबार फैल गया। विभिन्न शहरों में 'ईस्क्रा' के पाठकों और समर्थकों का संगठन खड़ा हो गया। ट्रान्स-कॉकेशिया में ऐसे ही एक संगठन के नेता थे स्तालिन। बाद में उनके सम्पादकत्व में जॉर्जिया में एक दूसरा राजनैतिक पत्र 'ब्राडजला' (संघर्ष) प्रकाशित हुआ।

आरएसडीएलपी का निर्माण

लेनिन के अखबार 'ईस्क्रा' की सफलता से पार्टी की दूसरी कांग्रेस को काफी मदद मिली। 1903 में लंदन में पार्टी की दूसरी कांग्रेस आयोजित हुई। इस कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था पार्टी-कार्यक्रम निर्धारित करना और उसे लागू करना। आरएसडीएलपी की लंदन कांग्रेस में जिन कार्यक्रमों को अपनाया गया, वे एक सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी के जुझारू आंदोलन के कार्यक्रम

(शेष पृष्ठ 4 पर)

109वीं जयंती पर देशभर में याद किये गये भगत सिंह

28 सितम्बर को पार्टी और इसके जनसंगठनों की विभिन्न इकाइयों द्वारा इस देश के महान सपूत के जज्बे से छात्र-नौजवानों को लैस करते हुए देश भर में शहीद-ए-आजम भगत सिंह की 109वीं जयंती मनाई गई। बड़ोदरा, गुजरात में भगत सिंह पर पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित की गई।



बड़ोदरा

भिवानी (हरियाणा) : आजादी आन्दोलन की समझौताहीन धारा के महान् क्रान्तिकारी शहीद भगत सिंह की 109वीं जयन्ती के अवसर पर 28 सितम्बर को स्थानीय नेहरू पार्क, भिवानी में ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गनाइजेशन (एआईडीवाईओ) की तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता राजेश दिनोद ने की। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉ. रामफल रहे। सभा का संचालन एआईडीवाईओ के जिला सचिव सन्दीप मेहरा ने किया। सभा को राजेश ने भी सम्बोधित किया। नरेश ने शहीद भगत सिंह पर रचित गाना गाया

शहीद भगत सिंह के जीवन-संघर्ष और क्रान्तिकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए मुख्य वक्ता कॉ. रामफल ने बताया कि भगत सिंह अदम्य साहस, देशभक्ति, ज्ञान की प्रगाढ़ता, सत्यान्वेषी मानसिकता, सांगठनिक दक्षता, छोटी उम्र में ही विचारों की गहराई, कुर्बानी व धर्मनिरपेक्षता की अनुकरणीय मिसाल पेश कर गये थे। उनके प्रति अपने दिल में गहरे आदरभाव के साथ देशवासियों ने उन्हें शहीद-ए-आजम के विशेषण से नवाजा था। आज भी छात्र-नौजवानों और आम लोगों के वे प्रेरणा स्रोत हैं। वे न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गुलामी की जंजीरों से देश को आजाद कराना चाहते थे, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें इंसान को अपनी बुनियादी

आवश्यकताओं के लिए तरसना न पड़े और मानव द्वारा मानव का शोषण न हो।

ऑल इण्डिया डी.वाई.ओ. भिवानी जिला सचिव सन्दीप मेहरा ने बताया कि 15 अगस्त, 1947 को समझौते से आजादी तो मिली परन्तु अंग्रेज साम्राज्यवादियों की जगह भारतीय पूँजीपति राजसत्ता पर काबिज हो गए। इस तरह शासक-शोषक ही बदले और शोषण-जुल्म बदस्तूर जारी है। हर तरह के शोषण से मुक्ति का शहीद भगत सिंह का सपना आज भी अधूरा है। आजादी के इन 69 सालों के दौरान अमीर और अमीर होते गये तथा गरीब और भी गरीब। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, तंगहाली बढ़ती जा रही है। पढ़ाई-लिखाई और इलाज महंगा होने से आम आदमी की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। प्रचार माध्यमों से अश्लीलता, यौनता व हिंसा परोसी जा रही है। शराबखोरी, नशाखोरी, जुए और लाटरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह लोगों को, खासकर छात्र-नौजवानों को सांस्कृतिक-नैतिक पतन की ओर धकेला जा रहा है। महिलाओं पर अपराध, बलात्कार, अत्याचार बढ़ रहे हैं। राजनीति के नाम पर चल रहा है भ्रष्टाचार और मौकापरस्ती। देशसेवा की आड़ में की जा रही है पूँजीपतियों की स्वार्थपूर्ति। जातिवाद, साम्प्रदायिकता व क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर मेहनतकश जनता में फूट डाली जा रही है। भगत सिंह जैसे क्रान्तिकारियों की याद को शासक वर्ग जनमानस से भुला देना चाहता है ताकि उनके जीवन-संघर्ष से प्रेरित होकर और सीख लेकर कोई इस शोषण-जुल्म का विरोध न कर सकें।

सभा में रजत जांगड़ा, पवन, राजेश, विशाल, पूजा, प्रीतम, सोनू, ममता, जयवीर व छैलूराम आदि भी शामिल हुए।



रेवाड़ी

नवा गढ़ी मुंगेर में दो दिवसीय चिकित्सा शिविर सम्पन्न

मुंगेर (बिहार) : मेडिकल सर्विस सेंटर एवं एआईडीवाईओ के संयुक्त तत्वावधान में बाढ़ पीड़ितों के लिए दो दिवसीय चिकित्सा शिविर 19 सितम्बर को नवा गढ़ी उच्च विद्यालय मुंगेर के प्रांगण में सम्पन्न हुआ। मेडिकल सर्विस सेंटर के डॉ. हरीकृष्ण मायती, डॉ. ललित घोष की छह सदस्यीय टीम को जमालपुर मुंगेर शहर के दर्जनों नामचीन चिकित्सकों और आम लोगों, खासकर बाढ़ क्षेत्र के नौजवानों द्वारा दिया गया स्वतः स्फूर्त सहयोग उल्लेखनीय है। डॉ. श्रवण ठाकुर, डॉ. बी जे बोस, डॉ. राजीव गुप्ता, डॉ. कविता, आर लाल, डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. अमित, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. राकेश आदि के सहयोग से लगभग दो हजार मरीजों का इलाज सम्भव हो सका।



गीत-संगीत व वाद-विवाद प्रतियोगिता



जौनपुर (उ.प्र.) : 18 सितम्बर को महान साहित्यकार शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर श्रीरामचंद्र शिक्षा निकेतन खजुरन, जौनपुर के प्रांगण में किशोर संगठन कॉम्सोमोल के तत्वावधान में गीत-संगीत व वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के 72 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार दिये गये। निर्णायक मण्डल में हौसिला प्रसाद सरोज ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉ. मिथिलेश मौर्य ने की। मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी), बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉ. राजकुमार चौधरी ने वर्तमान में पूँजीवादी शासन-व्यवस्था में मानवीय मूल्यबोधों व नैतिकता में गिरावट व संवेदनहीनता से बचने के लिए शरत साहित्य को बारीकी से पढ़ने, समझने और जीवन में उतारने पर बल दिया। शरतचंद्र चटर्जी ने साहित्य के क्षेत्र धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी क्रान्तिकारी विचारों को समाहित किया और साहित्य को सिर्फ कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए रचा। उन्होंने कहा कि आज भी शरत साहित्य की प्रासंगिकता है। शुरुआत में बच्चों ने पेरेंड की। सभी गणमाण्य व्यक्तियों ने शरतचंद्र के चित्र पर माल्यार्पण किया। 'हम होंगे कामयाब' गाने के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

छात्रों का धरना

रायपुर (छ.ग.) : राज्य में व्याप्त शैक्षणिक समस्याओं के खिलाफ ऑल इण्डिया डीएसओ द्वारा बूढ़ा तालाब, रायपुर में 21 सितम्बर को धरना दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री के नाम कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री हरीश पाटिल को मांग युक्त ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि आठवीं कक्षा तक पास-फेल प्रणाली पुनः चालू की जाये व 5वीं और 8वीं के बोर्ड पुनः बहाल किये जायें, राज्य में बंद किये गये 2918 स्कूलों को दोबारा चालू किया जाए, कॉलेजों में सिलेबस के अनुसार पर्याप्त संख्या में पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध कराई जायें, सभी कॉलेजों में आर्ट-साइंस-कॉमर्स कोर्स चालू किये जायें, सभी स्तर पर की गई फीस वृद्धि वापस ली जाये, ग्रेडेशन-सेमेस्टर प्रणाली रद्द की जाये, सीटें बढ़ाई जायें, स्ववित्त पोषित कोर्स, जनभागीदारी समिति, शाला विकास समिति के नाम पर लूट बंद की जाये, सभी स्कूल-कॉलेजों में आवश्यक संख्या में नियमित शिक्षक-प्राध्यापक नियुक्त किये जायें, सभी जिला मुख्यालयों व ब्लॉकों में होस्टल खोले जायें, राज्य बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाये, शिक्षा का निजीकरण-व्यापारीकरण व साम्प्रदायीकरण बंद किया जाये।

धरने में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर आदि जिलों के लगभग 100 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। धरने को एसयूसीआई(सी) के नेता कॉ. विश्वजीत हारोडे और एआईडीएसओ के छात्र नेता आत्माराम साहू, जतिन साहू, नीतू साहू, प्रवीण शर्मा, शुभम पाण्डेय, पूजा शर्मा, परमानंद साहू व सन्तू ने सम्बोधित किया।



रायपुर

एआईडीएसओ का स्कूल सम्मेलन

गुना (म.प्र.) : सरकारी स्कूलों में व्याप्त समस्याओं, कक्षा-8 तक पास-फेल प्रणाली पुनः चालू करने की मांग पर और मध्य प्रदेश के 1 लाख 8 हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ ऑल इण्डिया डीएसओ द्वारा स्थानीय मैथिल ओझा धर्मशाला में 4 सितम्बर को शासकीय क्रमांक-2, शासकीय एलएमबी उत्कृष्ट स्कूल का संयुक्त रूप से स्कूल छात्र सम्मेलन किया गया। इसके शुरू में जनगीत प्रस्तुत किये गये। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए संगठन की जिला कमेटी सदस्य मनोज रजक ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए जोरदार छात्र आन्दोलन गठित करने की जरूरत है। उन्होंने पूर्व में किये गये आन्दोलनों की सफलता का जिक्र किया।

सम्मेलन में विभिन्न स्कूलों की कमेटियों का गठन किया गया। शा. क्र.-2 स्कूल कमेटी के अध्यक्ष गिरीज, उपाध्यक्ष सतपाल कितर व सचिव रवि केवट, शा. एम.एल.बी. स्कूल में अध्यक्ष रानी कुशवाह, सचिव संगीता कुशवाह तथा शा. उत्कृष्ट के अध्यक्ष समरथ सिंह पाल व सचिव दीपक चुने गये। कार्यक्रम में राजुल श्रीवास्तव, सोनम शर्मा, सुनील सेन ने कमेटियों के गठन के सांगठनिक प्रस्ताव पेश किये। संचालन प्रमोद नामदेव ने किया।

महान नवम्बर क्रांति...

(पृष्ठ 2 का शेष)



थे। कहा गया कि पार्टी का मकसद है उत्पादन के साधनों से व्यक्तिगत मालिकाना खत्म करना, मानव द्वारा मानव का शोषण और वर्ग-विभाजित समाज का खात्मा करना। संक्षेप में, पूँजीवादी व्यवस्था का खात्मा करना और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना। कार्यक्रम में कहा गया कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाजवादी क्रांति करनी होगी और सर्वहारा वर्ग का राज कायम करना होगा। इसके लिए सबसे पहले निरंकुश जारशाही का खात्मा करना जरूरी है।

लेकिन महज कार्यक्रम निर्धारित कर लेने से ही काम नहीं चलता। पार्टी का सांगठनिक ढाँचा कैसा होगा और पार्टी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कैसे करेगी - इस संबंध में स्पष्ट रूपरेखा तय करना बेहद जरूरी हो गया। पार्टी के सांगठनिक नियमों के बारे में फैसला करना बहुत जरूरी हो गया। इन विषयों को लेकर पार्टी की दूसरी कांग्रेस में जबर्दस्त बहस शुरू हो गई। खास तौर पर बहस इस बात को लेकर शुरू हुई कि पार्टी के सदस्य कौन हो सकते हैं और कौन नहीं। दूसरी कांग्रेस में पार्टी में दो ग्रुप बन गये। लेनिन के नेतृत्व में जो बहुसंख्यक समूह था उसका नाम हुआ 'बोलशेविक' और अल्पसंख्यक समूह का नाम हुआ 'मेशेविक'। शुरू में प्लेखानोव लेनिन के साथ थे। लेकिन बाद में वे मेशेविकों की ओर चले गये।

मेशेविकों की मांग थी कि हर प्रोफेसर, हर छात्र, "हर हड़ताली" को, हर प्रदर्शनकारी को यह अधिकार दिया जाये कि वह खुद को पार्टी का सदस्य घोषित कर सके, विभिन्न विचारधाराओं वाले समूहों और व्यक्तियों को पार्टी की सदस्यता दी जाये। साथ ही बहुमत के प्रति अल्पमत के समर्पण की नीति को भी छोड़ दिया जाये। मेशेविक केन्द्रीयता की नीति के विरोधी थे। वे स्वतंत्र व्यक्ति-चिंतन के समर्थक थे। वे पार्टी को लुंज-पुंज राष्ट्रीय पूछल्लावादी ('खवोटिस्ट') पार्टी बना देने के पक्षधर थे। वास्तव में रूस में तब बुर्जुआ जनवादी क्रांति दस्तक दे रही थी। इसलिए बुर्जुआ बुद्धिजीवी क्रांति के पक्ष में खड़े होकर अनेक समय पार्टी के काम में मदद करते थे। यही वजह है कि मेशेविकों ने इन्हें पार्टी सदस्य बनाने की कोशिश की।

लेनिन का लक्ष्य था सर्वहारा वर्ग की एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करना। मेशेविकों की अति क्रांतिकारिता और अराजक गतिविधियों के खिलाफ खड़े होकर लेनिन मजदूर वर्ग की एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करना चाहते थे, जिसका ढाँचा होगा मानव-देह जैसा (monolithic)। लेनिन के नेतृत्व में बोलशेविकों ने दृढ़ता के साथ एलान किया:

1. मजदूर वर्ग और मजदूर वर्ग की पार्टी एक नहीं होती। मजदूर वर्ग की पार्टी उस वर्ग का वर्ग-सचेत और मार्क्सवादी विचारधारा से लैस अगुआ हिस्सा होती है।

2. पार्टी सिर्फ अगुआ हिस्सा ही नहीं है, मजदूर वर्ग का सबसे संगठित अगुआ दस्ता होती है। संगठन ही सर्वहारा वर्ग का एकमात्र हथियार होता है। इसलिए पार्टी सदस्यों को अनिवार्य रूप से किसी न किसी संगठन का सदस्य होना होगा।

3. सही तरीके से काम करने और जनता को अनुशासित तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए मजदूर वर्ग को केन्द्रीयता की नीति के आधार पर पार्टी को संगठित करना होगा। यानी पार्टी में नेतृत्व को स्थापित करना होगा, निचले स्तर की कमेटियों को उच्चतर स्तर की कमेटियों के प्रति समर्पण भाव रखना होगा। पार्टी

के हर स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी का अनुशासन लाजिमी तौर पर मानना होगा।

4. संगठन का उच्चतम रूप है पार्टी। पार्टी ही दूसरे तमाम संगठनों को नेतृत्व प्रदान करेगी। इसलिए उन्नत विचारधारा से लैस, वर्ग-संघर्ष के कायदे-कानून और क्रांतिकारी आंदोलन के अनुभव से समृद्ध मजदूर वर्ग के सबसे अगुआ हिस्से को लेकर पार्टी निर्मित होगी।

5. आम मजदूरों के साथ पार्टी का रिश्ता कायम होना काफी जरूरी है। बगैर इसके मजदूरों की तरक्की नहीं होगी।

6. पार्टी कभी भी 'खवोटिस्ट' यानी पूछल्लावादी पार्टी नहीं बनेगी। समाज में घट रही घटनाओं को अपनी स्वतःस्फूर्तता पर छोड़ कर पार्टी घटना के पीछे-पीछे नहीं चलेगी। लेनिन ने दिखाया था कि "क्रांतिकारी सिद्धांत के बगैर क्रांतिकारी आंदोलन निर्मित नहीं हो सकता। सबसे उन्नत सिद्धांत द्वारा संचालित होने पर ही कोई पार्टी मजदूर वर्ग के अगुआ दस्ते की भूमिका निभा सकती है। ... स्वतःस्फूर्तता के जो हिमायती हैं, जो चेतना की भूमिका को नजरअन्दाज करते हैं, पार्टी की भूमिका को गौण कर देते हैं, वे इसके जरिये जाने-अनजाने मजदूरों के अंदर बुर्जुआ विचारधारा के प्रभाव को फैलाने में ही मदद पहुँचाते हैं"।

'एक कदम आगे दो कदम पीछे' ('One step forward two step back') नामक प्रसिद्ध पुस्तक में लेनिन ने पहली बार मार्क्सवाद के इतिहास में पार्टी की भूमिका की चर्चा की। उन्होंने दिखाया कि सर्वहारा वर्ग का नेतृत्वकारी संगठन, पार्टी उसका मुख्य हथियार है। इसके बगैर मजदूर वर्ग की कोई भी क्रांति, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना का संघर्ष असंभव है।

रूस के ज्यादातर सोशल डेमोक्रेटिक संगठनों ने बोलशेविकों का साथ दिया। उस दौरान कॉमरेड स्तालिन जेल में थे। पार्टी की दूसरी कांग्रेस के फैसलों के बारे में जानकारी होने पर उन्होंने लेनिन के नेतृत्व में बोलशेविकों को ही अपना समर्थन दिया।

इसके बाद बोलशेविक मजदूर वर्ग के आंदोलन को संगठित करने के काम में कूद पड़े। 1901 से 1904 के दौरान रूस में आंदोलन की काफी तरक्की हुई। 1904 में रूस-जापान की लड़ाई छिड़ गई। जार सरकार की उम्मीद थी कि यह लड़ाई क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति को रोक देगी। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरकर बोलशेविकों ने 1904 के दिसम्बर में बाकू तेल क्षेत्र में एक विशाल हड़ताल संगठित की और इसके प्रभाव में आकर देश भर में हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा। ये सारी हड़तालें मानो वज्रनिनाद की तरह देश में आने वाली क्रांति का संदेश दे गयीं।

1905 का पहला क्रांतिकारी उभार

पहले ही कहा जा चुका है कि 1903 में दूसरी कांग्रेस में एक एकीकृत पार्टी का ढाँचा लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (आरएसडीएलपी) के आविर्भाव के बावजूद पार्टी की स्थिति मानो एक शरीर में दो आत्माओं जैसी थी। लेनिनवादी कार्यकर्ता 'बोलशेविक' के नाम से और मातोंव, ट्रॉट्स्की आदि नेताओं के अनुयायियों को 'मेशेविक' के नाम से जाना जाता था। प्लेखानोव पहले तो लेनिन के साथ थे, पर बाद में उनका झुकाव मेशेविकों की ओर होता गया और एक समय में आकर 'ईस्क्रा' पर 'मेशेविकों' का कब्जा हो गया। पार्टी के सांगठनिक नियम-सिद्धांतों के बारे में मेशेविक अपनी राय 'ईस्क्रा' के जरिये प्रकट करते रहे।

इसी बीच, 'ईस्क्रा' के साथ-साथ पार्टी की केन्द्रीय कमेटी भी बोलशेविकों के नियंत्रण से बाहर चली गयी। लेकिन, लेनिन की पुस्तक 'एक कदम आगे दो कदम पीछे' ने संगठन संबंधी मेशेविकों की अवसरवादी धारणाओं को चकनाचूर कर दिया और पार्टी के नेता-कार्यकर्ताओं के बीच एक साफ विभाजन रेखा खींच दी।

ऐसी स्थिति में बोलशेविक पार्टी की तीसरी कांग्रेस की तैयारी में लगे रहे। 1904 के अगस्त में लेनिन के संचालन में स्विट्जरलैंड में बोलशेविकों का सम्मेलन आयोजित हुआ। अगले साल की शुरुआत में ही उन्होंने अपना मुखपत्र 'व्येपोंद' (आगे बढ़ो) प्रकाशित किया। इस तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो धड़ों में बँट गयी। पार्टी के अंदर जब संघर्ष तेज हो रहा था, ठीक

उसी समय रूस में जन आंदोलन भी तीव्र हो रहा था। एक तरफ 1904 में आरंभ हुए रूस-जापान के साम्राज्यवादी युद्ध से छुटकारा पाने की ख्वाहिश थी, तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ते शोषण में जकड़े किसान-मजदूरों का संघर्ष हिलोरे ले रहा था। 1905 का साल रूस के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। साल की शुरुआत में ही जन आंदोलन का उफान पैदा हो गया था। इस दौर की एक खास घटना थी 'रक्तरंजित रविवार'। 9 जनवरी को करीब डेढ़ लाख मजदूर और उनके परिवारजन सेंट पीटर्सबर्ग में जार के महल के सामने इकट्ठे हुए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पादरी गापन कर रहे थे। चूँकि इस आंदोलन में काफी संख्या में मजदूर शामिल थे, इसलिए आंदोलन का हथ्र चाहें जो भी हो, लेनिन के नेतृत्व में बोलशेविक भी इस आंदोलन में शामिल हुए। निहत्थे मजदूरों के इस जमावड़े में जार की सेना द्वारा चलायी गोली से एक हजार लोगों ने अपनी जान गवायीं। हजारों मजदूर घायल और गिरफ्तार हुए। इस खूनी घटना से सारा रूस हिल उठा। हड़ताल, बैरिकेड (मोर्चाबंदी) और प्रतिरोध आंदोलन से पूरे रूस में क्रांति का ज्वार-सा आ गया। पोटम्किन जंगी जहाज के नाविकों और नौसेना की बगावत इस समय की एक उल्लेखनीय घटना थी। आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए जार ने तमाम जनता को मताधिकार प्रदान कर 'ड्यूमा' (जार शासित रूसी संसद) के चुनाव का एलान कर दिया। लेकिन बोलशेविकों ने उस का बहिष्कार कर जन आंदोलन को और आगे बढ़ाने की घोषणा की।

1905 के दिसम्बर महीने में बोलशेविक पार्टी ने दूसरी ताकतों के साथ मिलकर चौतरफा हथियारबंद बगावत शुरू कर दी। लेकिन जार ने इसके खिलाफ सारी ताकतों को इकट्ठा कर जबर्दस्त हमला बोल कर क्रांति की इस कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। मेशेविकों ने 'देशप्रेम' की मानसिकता से जार के युद्ध-प्रयासों को समर्थन दिया और वे उदारवादी बुर्जुआ वर्ग पर पूरी तरह से निर्भरशील रहे। लेकिन लेनिन ने 1905 की रूस की इस बुर्जुआ जनवादी क्रांति को दूसरे रूप में चिह्नित किया। उन्होंने कहा कि यह घटना ऐसे समय में घटित हो रही है जब विश्व पूँजीवाद साम्राज्यवाद के स्तर पर पहुँच गया है। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा, "इस बुर्जुआ जनवादी क्रांति में सर्वहारा वर्ग ही नेता की भूमिका निभायेगा।" उनकी राय में जीत हासिल करने के लिए यह क्रांति मजदूर वर्ग के नेतृत्व में संचालित होनी चाहिए। यही वजह है कि बोलशेविक हथियारबंद बगावत के जरिये जार के शासन का खात्मा कर मजदूर-किसानों के प्रतिनिधियों को लेकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। आम आदमी को हथियारों से लैस करने पर मेशेविकों की ओर से प्लेखानोव ने जोरदार एतराज जताया। मेशेविकों के इसी विश्वासघात का फायदा उठाकर निरंकुश जार सरकार ने क्रांतिकारी आंदोलन पर जबर्दस्त हमला बोल दिया। क्रांतिकारी बगावत को वापस ले लिया गया। लेनिन ने कहा, "1905 से 1907 - इन तीन सालों के बहादुराना संघर्ष के जरिये रूस के सर्वहारा वर्ग ने अपने लिए और रूसी जनता के लिए जो सहूलियतें हासिल की हैं, उन्हें हासिल करने में अन्य देशों को कई युग लगे हैं। इस

(शेष पृष्ठ 6 पर)

पिछले 3 सालों में भारत सरकार द्वारा उद्योगपतियों के माफ किये टैक्स की मात्रा

| | |
|---------|------------------------|
| 2013-14 | 5, 49, 984 करोड़ रुपये |
| 2014-15 | 5, 54, 349 करोड़ रुपये |
| 2015-16 | 6, 11, 128 करोड़ रुपये |

क्या आप जानते हैं?

प्रधानमंत्री के बेहद करीबी, एकाधिकारी पूंजीपति गौतम अडाणी द्वारा बैंकों से लिया गया कुल 72, 000 रुपये का कर्ज किसानों द्वारा लिये गए कुल कर्ज के बराबर है। जबकि अडाणी साहब कर्ज चुकाने में मजे से डिफाल्टर हो रहे हैं, फसलों के लाभकारी दाम न मिलने या फसल खराब हो जाने की वजह से कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाने पर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं।

कोलकाता में महिलाओं द्वारा प्रदर्शन



शराब पर रोक लगाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस), पश्चिम बंगाल की कार्यकर्ताओं ने 20 सितम्बर को कोलकाता में रैली की। दिल्ली की गलियों में एक युवती की सरेआम क्रूरता से की गई हत्या के खिलाफ राज्यपाल भवन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसी तरह के कार्यक्रम सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार में भी किये गये।

केकेएमएस ने सौंपा ज्ञापन

तोशाम (हरियाणा) : बाजरे सहित विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने, पंचायती भूमि पर सरकारी दखलअंदाजी बंद करने, पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पास-फेल प्रणाली चालू करने आदि मांगों को लेकर 28 सितम्बर को ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम देवीलाल सिहाग को सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई कि फसलों के लाभकारी दाम दिये जायें जो लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक हों, फसलों के खराबे पर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, पंचायती व शामलात भूमि पर सरकारी दखलअंदाजी बंद की जाये, मनरेगा में दैनिक मजदूरी 5 सौ रुपये दी जाये, पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पास-फेल प्रणाली पुनः चालू की जाये, बुढ़ापा पेन्शन पर लगाई गई तमाम शर्तें हटाई जायें, बेसहारा पशुओं का प्रबंध किया जाये। ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन के नेताओं ने कहा कि फसलों का समर्थन मूल्य बहुत कम है। इसकी तुलना में लागत ज्यादा आती है और किसानों का घाटे का सौदा होती जा रही है। उन्होंने समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रति गंभीरता दिखाने की सरकार से मांग की।

ज्ञापन देने वालों में संगठन के जिला प्रधान कॉमरेड जिले सिंह, जिला सचिव कॉ. रोहताश सैनी, उदयवीर, सुखवीर आदि कई पदाधिकारी शामिल थे।

शिक्षा की मांगों पर छात्रों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन

जौनपुर (उ.प्र.) : शिक्षा की विभिन्न समस्याओं को लेकर 30 अगस्त को ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) जौनपुर जिला कमिटी द्वारा जिला मुख्यालय पर छात्र प्रदर्शन किया गया। इसमें विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्र रेलवे स्टेशन परिसर में एकत्रित हुए। वहां से जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी हाथों में मांग पट्टिकाएं व झण्डे-बैनर लिए हुए नारे लगा रहे थे। जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों-पॉलीटेक्निक चौराहा, ओलदगंज चौराहा होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा। कार्यक्रम की अध्यक्षता एआईडीएसओ के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार खरवार ने की और संचालन जिला सचिव विकास कुमार मौर्य ने किया। सभा को राज्य उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार मौर्य व जिला कमिटी सदस्य संतोष प्रजापति और किरन मौर्य ने भी सम्बोधित किया। शशि मौर्य ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया। मुख्य वक्ता एआईडीएसओ के राज्य सचिव हरिशंकर मौर्य थे। अंत में 11 सूत्री मांगपत्रक जिलाधिकारी जौनपुर को सौंपा गया।

आसाम में एसयूसीआई(सी) ने की रैली



गुवाहाटी : आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने, 67 आयल रिगों के निजीकरण पर रोक लगाने और आसाम के बाढ़-पीड़ितों के पुनर्वास व राहत प्रदान की पर्याप्त व्यवस्था करने, बिना किसी धार्मिक व भाषाई भेदभाव के सभी भारतीय नागरिकों को समाविष्ट करने की मांगों को लेकर 30 अगस्त को एसयूसीआई(सी) की आसाम राज्य कमिटी के नेतृत्व में रैली की गई। धिगुलिपुकरी से चले विरोध प्रदर्शन को पुलिस द्वारा डी सी कार्यालय के पास रोक दिया गया।

रैली में एसयूसीआई(सी) के लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली को पार्टी की आसाम राज्य सचिव कॉमरेड चन्द्रलेखा दास ने सम्बोधित किया। उन्होंने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता में आते ही बीजेपी अपने वादे भूल गई। यह कालाबाजारी करने वालों के साथ सांठगांठ कर रही

है। जिन जमाखोरों, कालाबाजारियों, उद्योगपतियों और सिण्डीकेटों ने चुनाव के दौरान बीजेपी की मदद की थी उनको अब सरकार ने आम आदमियों को लूटने का लाइसेंस दे दिया है। कॉ. दास ने कहा कि भूमि कटाव को किसी भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। नदी का तल काफी बढ़ गया है जिससे जल्दी-जल्दी बाढ़ आ रही है। आयल रिगों को निजी हाथों में देना ओएनजीसी जैसे लाभ में चल रहे सार्वजनिक उद्योग का निजीकरण करने वाला कदम है। उन्होंने 'आसाम आन्दोलन' से हुए विध्वंसकारी परिणामों की याद दिलाते हुए और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार अंधराष्ट्रवादी ताकतों के साथ मिलकर एनआरसी को बढ़ाने के नाम पर लाखों लोगों को बेघर करेगी तो आसाम आगे और भी विघटित हो जाएगा। सभा के बाद एडीसी, कामरूप को एक ज्ञापन सौंपा गया।

केरल राज्य शिक्षा बचाओ सम्मेलन

तिरुवनंतपुरम : ऑल इण्डिया सेव एज्यूकेशन कमिटी, केरल राज्य चैप्टर की ओर से 20 अगस्त को यहां बैंक इम्प्लाइज यूनियन हाल में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. के एन एन कुरूप ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कमाई का मौका देने के लिए, जैसाकि नई शिक्षा नीति 2016 में पेश किया गया है, केन्द्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह 1986 में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रतिपादित एनईपी'86 की उसी नीति को जारी रख रही है। केरल के सभी जिलों से आये प्रतिनिधियों ने अपनी चिंता जाहिर की। संगठन के

राज्य उपाध्यक्ष डॉ. वी. वेणुगोपाल ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्य सचिव सजर खान ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें मांग की गई कि जन शिक्षा को केवल तभी बचाया जा सकता है जब वर्तमान पाठ्यक्रम को पूरी तरह तिलांजलि दे दी जाये और इससे बढ़िया क्वालिटी का पाठ्यक्रम चालू किया जाये। उन्होंने शिक्षा के व्यावसायीकरण-व्यापारीकरण की कड़ी आलोचना की। प्रो. एन.सी. हरिदास, प्रो. के.वी. थोमाकुट्टी, श्री कायिकारा बाबू, श्री जी. नारायणन और श्री शशिकुमार ने भी सभा को सम्बोधित किया। कमिटी ने दोहराया कि शिक्षा का व्यापारीकरण और साम्प्रदायीकरण एक फासीवादी कदम है।

गांव शामलात व रद्द हो चुके सेज की भूमि उद्योगपतियों को देने की नीति का विरोध

रोहतक, हरियाणा : ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन के हरियाणा राज्य सचिव कॉ. जयकरण ने 19 अगस्त को प्रेस को जारी किये एक बयान में कहा कि गाँव की शामलात भूमि को उद्योगपतियों को देने की नीति का एआईकेकेएमएस कड़ा विरोध करता है। उन्होंने हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल द्वारा गत दिनों चण्डीगढ़ में इस आशय के दिये गये बयान की कड़ी निन्दा की जिसमें उन्होंने गाँव शामलात भूमि के अलावा बादली क्षेत्र के रद्द हो चुके एस.सी.जैड.(सेज) की जमीन को उद्योगपतियों को देने की बात की है। किसान नेता कॉ. जयकरण माण्डौठी ने कहा कि गाँव शामलात भूमि (बणी, चरागाह, आदि) के इस्तेमाल पर ग्राम सभा को छोड़कर अन्य किसी का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा सरकार द्वारा इस अधिकार को छीना जाना लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की यह कुचेष्टा पूर्णतया अनैतिक व कानून के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में स्पष्ट कह चुका है कि गाँव शामलात भूमि पर ग्राम सभा का अधिकार प्राचीन काल से चला आ रहा है जो न्यायसंगत व कुदरतन है। इसके बावजूद केन्द्र की मोदी सरकार की पहल पर गाँव शामलात भूमि पर प्रदेश की भाजपा सरकार बेजा हस्तक्षेप कर रही है और गुपचुप तरीके से इस बारे में अनैतिक काम को कानूनी जामा भी पहना रही है। एआईकेकेएमएस इसका पुरजोर विरोध करता है और सरकार से इस कदम को तत्काल वापस लेने की माँग करता है।

बैंक कर्मियों की सभा आयोजित

मुरादाबाद (उ.प्र.) : पंजाब नेशनल बैंक इम्प्लाइज यूनिटी फोरम उ.प्र. के मुरादाबाद मण्डल के प्रतिनिधियों की एक सभा 18 सितम्बर को जलकल कर्मचारी संघ कार्यालय में हुई। सभा की अध्यक्षता संजय भटनागर ने की एवं संचालन भूपेन्द्र सिंह ने किया। सभा को फोरम के प्रदेश महासचिव कॉ. विजयपाल सिंह ने सम्बोधित किया। सभा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण, बैंकों का मर्जर, बैंकों में लगातार बढ़ता एनपीए और काम के बढ़ते बोझ के हिसाब से पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति न होने आदि प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एनपीए बढ़ता जा रहा है लेकिन कर्मचारियों द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद सरकार उन डिफाल्टरों के नाम तक नहीं बता रही है। बड़े-बड़े उद्योगपति घराने बैंकों का अरबों-खरबों रुपया मारें बैठे हैं। उनसे वसूली करने की बजाय सरकार उनको बैंकों का मालिकाना और देना चाहती है। बैंकों में बढ़ रही ठेकेदारी प्रथा पर भी चिंता व्यक्त की गई।

सभा में पंजाब नेशनल बैंक की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। सभा में उपस्थित ऑल इण्डिया बैंक इम्प्लाइज यूनिटी फोरम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ. गौरी शंकर दास ने बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर स्थानीय स्तर से शुरू कर देशव्यापी आन्दोलन चलाया जाएगा। इसी क्रम में बजट सत्र के दौरान संसद पर प्रदर्शन किया जाएगा। 16 नवम्बर को उ.प्र. में राज्य स्तर पर कन्वेंशन किया जाएगा। सभा में फोरम की मुरादाबाद जिला कमिटी का चुनाव किया गया जिसमें संजय भटनागर को जिला अध्यक्ष और भूपेन्द्र सिंह को जिला सचिव चुना गया।

महान नवम्बर क्रांति...

(पृष्ठ 4 का शेष)

संघर्ष ने विश्वासघातक, घृणित और मरणासन्न उदारतावाद के प्रभाव से मजदूर वर्ग को मुक्त किया है। इसने रूस के तमाम शोषित-पीड़ित लोगों को क्रांतिकारी जन आन्दोलन निर्मित करने की ताकत दी है।” रूस की यह पहली क्रांति सफल तो नहीं हुई, पर यह पूरी दुनिया में लोगों के मुक्ति-संग्राम को तेज करने में काफी कारगर साबित हुई।

इस असफल क्रांति ने ही रूस को दुनिया की क्रांति के मुख्य केन्द्र में तब्दील किया और लेनिन की बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में संचालित रूस का सर्वहारा वर्ग क्रांति के अगुआ दस्ते में तब्दील हुआ। आम जनता की नजरों में रूस के मुख्य सिद्धांतकार, संगठकर्ता और नेता के रूप में लेनिन का आविर्भाव हुआ। लेकिन 1905 की क्रांति की असफलता ने आम आदमी के जेहन में मायूसी भी पैदा की। लेनिन के महान प्रेरणादायी नेतृत्व ने ही जनता को हताशा के चंगुल से आजाद कर सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी संघर्ष को संगठित करने के लिए उसमें फिर नई जान डाल दी थी। क्रांति को ताकतवर बनाने के एकमात्र मकसद को लेकर क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाने में संघर्ष का रास्ता काफी ऊबड़-खाबड़ और जटिल था। लेकिन इतनी मुसीबतों के बीच भी लेनिन सही दिशा में आगे बढ़े थे।

इसी बीच अप्रैल महीने में लंदन में पार्टी की तीसरी कांग्रेस आयोजित हुई। मेशेविकों ने एक साथ कांग्रेस आयोजित करने में अपनी असहमति जताकर अलग सम्मेलन आयोजित किया। इस घटना को लेनिन ने इस रूप में चिह्नित किया कि ‘दो कांग्रेस-दो पार्टियां’। मेशेविकों की भ्रात और अवसरवादी नीति के जवाब में इसी साल जुलाई में लेनिन की पुस्तक ‘जनवादी क्रांति में सोशल डेमोक्रेसी के दो रणकौशल’ प्रकाशित हुई।

क्रांति की कोशिश ऊपरी तौर पर नाकाम हो जाने से बोल्शेविकों ने दिसम्बर में नये तरीके से आंदोलन गठित करने की तैयारी शुरू की। आंदोलनकारी मजदूरों के बीच पार्टी की ताकत को बढ़ाने की आवाज उठी। इस दौरान दोनों धड़ों के बीच एकता की बात भी चर्चा का विषय बनी। लेनिन ने इस प्रस्ताव से सहमत होकर मेशेविकों के समक्ष एकता सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। 1906 के अप्रैल महीने में स्वीडन के स्टॉकहोम में ‘एकता सम्मेलन’ के नाम से मशहूर आरएसडीएलपी की चौथी कांग्रेस आयोजित हुई। नयी केन्द्रीय कमेटी में बोल्शेविकों की संख्या कम थी। हालांकि आगे चलकर इसी एकता के जरिये देश के विस्तृत हिस्सों में विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में मेशेविकों के साथ जुड़े बहुत सारे होनहार और अच्छे कार्यकर्ताओं व संगठनकर्ताओं को बोल्शेविक विचारधारा के साथ नजदीकी रिश्ता कायम करने का मौका मिला। मेशेविकों की अवसरवादी मानसिकता उनके समक्ष धीरे-धीरे उजागर होती गई।

इधर जार ने ‘दूसरी ड्यूमा’ की घोषणा कर दी। बोल्शेविकों ने नये सिरे से जन आंदोलन की ताकत जुटाने के लिए ड्यूमा में शामिल होने का फैसला किया। 1905 की क्रांति असफल होने के चलते जनता में निराशा घर कर गयी थी। ऐसी स्थिति में लेनिन चाहते थे कि क्रांतिकारी लोग ड्यूमा में शिरकत कर जनता के सामने मौजूदा समाज-व्यवस्था के निकम्पेपन को उजागर करें। ड्यूमा के संबंध में जनता का मोहभंग हो और वह क्रांति के समर्थन में आगे आये। इसी तरह से लेनिन ने दिखाया कि क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत से दो भिन्न परिस्थितियों में किस तरह से मार्क्सवादियों के फैसले भी भिन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा, “1905 में बुल्गान ड्यूमा का बॉयकाट करने का रणकौशल उस परिस्थिति में बिल्कुल सही रणकौशल था। ... वक्त आ गया है, जब क्रांतिकारी सोशल डेमोक्रेटों को निश्चित तौर पर बॉयकाट का रणकौशल छोड़ना होगा। 1906 में जब दूसरी ड्यूमा का गठन किया जायेगा (“अगर” गठन हुआ तो), तब उसमें शामिल होने में हम भी पीछे नहीं रहेंगे।” (Collected works, vol 2, P 142-145)। लेनिन ने यह भी दिखाया, “कभी संसद के अंदर संघर्ष, तो कभी संसद के बाहर संघर्ष, कभी संसद में भागीदारी करने, तो कभी उसका बॉयकाट करने का रणकौशल अपनाया

और इस तरह से संघर्ष के विभिन्न रूपों के आपसी संबंध और सम्पर्क-सूत्र, ये सारी बातें खास महत्व की थीं। ..1905 में बोल्शेविकों द्वारा पार्लियामेंट बॉयकाट की घटना ने क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग को अमूल्य राजनैतिक अनुभवों से समृद्ध किया है और दिखाया है कि कानूनी व गैर कानूनी, संसदीय व गैर-संसदीय विभिन्न आंदोलनों को जब संयोजित किया जाता है, तो कभी-कभी आंदोलन के संसदीय रूप का परित्याग करना सिर्फ अच्छा ही नहीं, बल्कि जरूरी भी होता है। लेकिन, इस अनुभव की नकल कर, जाँच-परख किये बगैर दूसरी परिस्थिति में अंधे की तरह प्रयोग करने से महा अनर्थ होगा... । बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग की पार्टी के ‘कोर’ की रक्षा (ताकतवर और उन्नत करना तो दूर रहा) ही नहीं कर पाते, यदि वे कठिन-कठोर संघर्ष के जरिये इस दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रख पाते कि कानूनी और गैर कानूनी, दोनों किस्मों के संघर्ष का संचालन करना जरूरी फर्ज है और यहाँ तक कि घोर प्रतिक्रियावादी पार्लियामेंट में शामिल होना भी जरूरी फर्ज है” (‘वामपंथी कम्युनिज्म एक बचकाना मर्ज’)

आज, जब पार्लियामेंट(संसद) के अंदर के आंदोलन के साथ बाहर के आंदोलन को संयोजित करने के मामले में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में लेनिन की यह सीख काफी महत्वपूर्ण है। जब तक क्रांतिकारी आंदोलन की लहर पूरे देश में नहीं फैल जाती, जब तक बुर्जुआ संसदीय राजनीति से जनता का मोहभंग नहीं हो जाता, तब तक संसद के बाहर के आंदोलन की आवाज की गूँज को संसद के अंदर पहुँचाने के लिए संसदीय मंच का जहाँ तक हो सके, इस्तेमाल करने की जरूरत रहेगी। पूँजीवादी शोषण से निजात दिलाने के सवाल पर बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था बिल्कुल निकम्मी है- संसद में शिरकत करते हुए इस सच्चाई से जनता को अवगत और सचेत किया जा सकता है। क्रांतिकारी विचारधारा से लैस होकर आम जनता जब आर-पार की आखिरी लड़ाई के लिए आगे बढ़ेगी, सिर्फ तभी संसदीय आंदोलन की जरूरत खत्म होगी और संसद का बहिष्कार करने की स्थिति पैदा होगी।

मेशेविकों ने भी ड्यूमा में शिरकत करने का फैसला लिया। लेकिन उनकी राय में यह फैसला था कि दूसरी संसदीय जनवादी पार्टियों के साथ मिलकर जार की मंशा पूरी करने के लायक एक ड्यूमा निर्मित करो, जन आंदोलन पर लगाम कसो। पार्टी की केन्द्रीय कमेटी में मेशेविकों का बहुमत रहने के चलते फैसला उनके पक्ष में जाने के आसार थे। समझौतापरस्ती के रुझान से मजदूर वर्ग और जन आंदोलन को बचाने के मकसद से बोल्शेविकों ने पार्टी कांग्रेस बुलाने की मांग की। 1907 के मई महीने में लंदन में पार्टी की पाँचवी कांग्रेस आयोजित हुई। ट्रॉट्स्की ने मध्यम-मार्ग पर चलने वाली एक पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। कांग्रेस में फैसला हुआ कि अब से पार्टी अन्य बुर्जुआ व पेटी बुर्जुआ पार्टियों, संसदीय जनवादियों, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों, पॉपुलर सोशलिस्टों आदि ताकतों के खिलाफ जोरदार वैचारिक संघर्ष चलायेगी। इसको बोल्शेविकों की एक विजय के रूप में दिखाते हुए कॉमरेड स्तालिन ने लिखा था, “क्रांतिकारी सोशल डेमोक्रेसी के परचम तले सारे रूस को अगुआ मजदूरों की एक पार्टी में शामिल करना सम्भव हुआ।” कांग्रेस आयोजित होने के कुछ दिनों के अंदर ही जार सरकार ने दूसरी ड्यूमा को भंग कर क्रांतिकारियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। 1907 के दिसम्बर महीने में लेनिन किसी तरह से गिरफ्तारी से बच कर विदेश चले गये।

स्टालिपिन की प्रतिक्रिया के दिन

1908-1912 का दौर रूसी क्रांतिकारियों के लिए काफी कठिन था। जार के मंत्री स्टालिपिन ने कई हजार क्रांतिकारियों को फाँसी पर लटका दिया। इस दौर को स्टालिपिन की प्रतिक्रिया (‘द स्टालिपिन रिएक्शन’) के दौर के रूप में जाना जाता है। इस दौर में यानी 1908 से 1912 तक बोल्शेविकों ने गैर कानूनी पार्टी संगठनों की रक्षा करने और पार्टी को मजबूत करने के लिए जहाँ तक सम्भव था, कानूनी अवसरों के इस्तेमाल का रास्ता अपनाया। लेनिन के शब्दों में, पार्टी ने जारशाही के खिलाफ आमने-सामने के प्रत्यक्ष संघर्ष का रास्ता छोड़कर



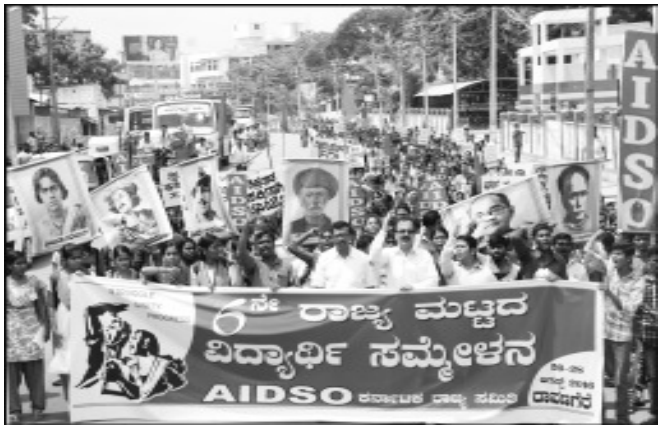
अप्रत्यक्ष रूप में संघर्ष चलाने का रास्ता अपनाया। हरेक कानूनी अवसर का फायदा उठाने की कोशिश जारी रखी। इस दौर में मेशेविकों ने काम-काज पूरी तरह से ठप कर दिया। तथाकथित बुद्धिजीवियों का यह कहना फैशन बन गया कि नयी स्थिति में मार्क्सवाद में सुधार-संशोधन लाना होगा। बोगदानोव, लुनाचारस्की, आदि बुद्धिजीवी मार्क्सवाद को ‘और विकसित’ करने के नाम पर इस महान सिद्धांत के मजबूत वैचारिक आधार को कमजोर कर रहे थे। इनके खिलाफ संघर्ष करने के बजाय प्लेखानोव सहित अन्य मेशेविक नेताओं ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया था। इस हमले के खिलाफ संघर्ष छेड़ कर मार्क्सवाद की समझदारी को वास्तविक तौर पर और विकसित करना लेनिन के लिए एक बेहद जरूरी काम हो गया था। इस दौरान लेनिन ने अपनी प्रख्यात पुस्तक ‘वस्तुवाद और अनुभवसिद्ध आलोचना’ (‘Materialism and Empirio Criticism’) की रचना की। उन्होंने माख, अवेनेरियस आदि की भाववादी सोच के खिलाफ सफल वैचारिक संघर्ष का संचालन किया। लेनिन ने दिखाया कि क्रांति के ज्वार के दौरान किस तरह से आगे बढ़ना होता है -कम्युनिस्टों को यह सीखना होता है। इसी तरह भाटे के दौरान, जब प्रतिक्रियावादी सोच आगे बढ़ रही होती है, तब कैसे काम करना होता है, किस तरह से पार्टी की हिफाजत करने के साथ-साथ उसे ताकतवर भी बनाना होता है, जो भी कानूनी सहूलियतें मिल रही होती हैं, उनका सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और जनता के साथ संबंध को और मजबूत कैसे किया जाता है -यह सब कुछ कम्युनिस्टों को अवश्य सीखना होगा। ... “ बोल्शेविकों ने काफी योजनाबद्ध ढंग से पीछे हटने का काम किया था, उनकी सेना का नुकसान भी बहुत कम हुआ था। “बोल्शेविक यह काम इसलिए कर पाये कि उन्होंने क्रांतिकारी लफ्फाजी करने वाले लोगों के चरित्र को स्पष्ट तौर पर जनता के सामने उजागर कर दिया था और उन्हें पार्टी से बहिष्कृत कर दिया था। ये लोग समझना ही नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारियों को अच्छी तरह से यह सीखना होता है कि कैसे घोर प्रतिक्रियावादी पार्लियामेंट के अंदर कानून से बच कर काम करना पड़ता है, कैसे घोर प्रतिक्रियावादी ट्रेड यूनियनों या इस तरह के अन्य संगठनों में काम करना पड़ता है?”

ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी पार्टी को अपने ज्ञान को और उन्नत करना होगा। मेशेविक तो नहीं, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक निश्चित तौर पर समझ गये थे कि आने वाले कई सालों के अंदर फिर से क्रांतिकारी आंदोलन का उभार पैदा होगा और इस नये उभार में जनता को शामिल करने की जिम्मेदारी पार्टी की ही होगी। लेनिन ने कहा, “क्रांति को भी एक अलग-थलग अकेला कार्यक्रम या घटना हरगिज नहीं समझना चाहिए(जैसा कि नदेज्दिन जैसे लोग सम्भवतः समझते हैं); वह तो एक ऐसा सिलसिला होता है जिसमें कमोबेश जोरदार जन विस्फोट और न्यूनाधिक निश्चल शांति के काल बारी-बारी से आते रहते हैं। यही वजह है कि हमारे पार्टी संगठन की गतिविधियों का प्रधान तत्व, इन गतिविधियों का केन्द्र, एक ऐसा कार्य होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा जोरदार विस्फोटों के काल में भी सम्भव तथा आवश्यक हो और पूर्ण शांति के काल में भी, यानी उसे राजनीतिक आन्दोलन का ऐसा काम होना चाहिए जो सारे रूस में फैला हो, जो जीवन के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाले और जो जनता के ज्यादा से ज्यादा व्यापक हिस्से के बीच हो।” (‘क्या करें’ वॉल्यूम-5 पेज-514)।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

बैंगलोर एआईडीएसओ का 8वां जिला सम्मेलन

बैंगलोर (कर्नाटक) : 18 सितम्बर को एआईडीएसओ की ओर से बैंगलोर में 8वां जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिग्री और स्नातकोत्तर कोर्सों के विभिन्न कॉलेजों से आये 300 छात्र प्रतिनिधियों ने शिरकत की। एसयूसीआई(सी) के बैंगलोर जिला सचिव डॉ. बी.आर. मंजूनाथ ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के बावजूद आम शिक्षा पाने का बुनियादी अधिकार अभी भी मृग-मरीचिका बना हुआ है। मुख्य अतिथि एआईडीएसओ के कर्नाटक राज्य अध्यक्ष डॉ. प्रमोद ने कहा कि 'अंतर्राष्ट्रीयकरण' के नाम पर शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण नई बुलन्दियों को छू रहा है। समापन भाषण संगठन के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष वी.एन. राजशेखर ने दिया। भावी संघर्ष को नेतृत्व देने के लिए एक नई जिला कमेटी गठित की गई।



बैंगलोर: सम्मेलन स्थल की ओर बढ़ते हुए छात्र प्रतिनिधि

एआईडीएसओ के द्वारा जिला सम्मेलन आयोजित

कटक (उड़ीसा) : 27-28 अगस्त को एआईडीएसओ की ओर से कटक जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की तैयारी में 400 जाने-माने लोगों को लेकर एक स्वागत कमेटी बनाई गई। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस देवप्रिय महापात्र थे। 27 अगस्त को बाराबाटी स्टेडियम से कॉलेज स्कवायर तक छात्रों का एक सुसज्जित जुलूस निकाला गया। वहां नेताजी की मूर्ति के सामने सभा की गई जिसका उद्घाटन एसयूसीआई (सी) की गुजरात राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव डॉ. द्वारकानाथ रथ ने किया। सभा को उड़ीसा डेली अखबार के सम्पादक डॉ. सत्य रे, डॉ. विश्वबाबू दास, डॉ. अशोक मिश्रा, डॉ. शिवाशीष प्रहराज ने भी सम्बोधित किया। 28 अगस्त को शहीद भवन कटक में प्रतिनिधि अधिवेशन किया गया। इसमें 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

इसका संचालन डॉ. बेबी बालाबंटारे, डॉ. रेखा दण्डपत और डॉ. निरुपमा बेहरा को लेकर गठित अध्यक्षमण्डल ने किया। जाने-माने न्यूरो सर्जन डॉ. भवानी शंकर दास, सामाजिक कार्यकर्ता श्री चित्तरंजन मोहंती, प्रसिद्ध

साहित्यकार डॉ. महेश्वर मोहंती, भवानीपटना (ऑटोनोंमस) कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. बाबाजी पटनायक, सलीपुर (ऑटोनोंमस) कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. अक्षय दास एवं ब्लॉक ग्रांट टीचर्स एसोसियेशन के नेता श्री करुणाकर सत्रुसाल ने विभिन्न शैक्षणिक-सांस्कृतिक समस्याओं पर चर्चा की। कला विकास केन्द्र, कटक के पूर्व प्रिंसिपल अरूपलाल घोष, ऑल इण्डिया रेडियो, कटक के पूर्व निदेशक श्री प्रसेनजीत मोहंती ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। छात्र आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए सम्मेलन में 76 सदस्यीय जिला कमेटी चुनी गई जिसमें अध्यक्ष डॉ. भाग्यरवि, उपाध्यक्ष डॉ. अभिराम बेहरा व डॉ. तरुणसेन नायक, सचिव डॉ. विनोद सेठी और कोषाध्यक्ष इशा धर को चुना गया।

बालांगीर : 21 अगस्त को बालांगीर जिला सम्मेलन स्थानीय अग्रसेन धर्मशाला में किया गया। इसमें 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इससे पहले शहर में एक शानदार जुलूस निकाला गया। जुलूस के बाद हुई सभा में डॉ. ओमप्रकाश साहू व डॉ. चित्तरंजन मिश्रा को लेकर एक अध्यक्षमण्डल गठित किया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता थे एआईडीएसओ के महासचिव डॉ. अशोक मिश्रा,

कॉमरेड चंदन सिंह लाल सलाम

रेवाड़ी (हरियाणा) :

एसयूसीआई(सी) की रेवाड़ी जिला कमेटी के सदस्य, वरिष्ठ किसान नेता कॉमरेड चंदन सिंह निमोट निवासी का 18 सितम्बर को निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन, पार्टी नेता- कार्यकर्ताओं के आचरण व समाज के क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर 1987 में वे पार्टी के आवेदक सदस्य उस वक्त बने जब प्रथम महासम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में कार्यकर्ताओं की एक सभा को सम्बोधित करने के लिए दिवंगत पार्टी महासचिव डॉ. नीहार मुखर्जी दिल्ली आये थे।

वे सेना की एज्यूकेशन कोर से रिटायर्ड हुए थे। प्रेमचंद, शरतचंद्र, शेक्सपीयर व जेएस मिल को उन्होंने पढ़ा था। वे जात-पात से ऊपर थे, वे धर्मनिरपेक्ष मूल्यबोधों व ईमानदारी को अपने जीवन में अपना कर चले। पार्टी कॉमरेडों के लिए गार्जियन की भूमिका वे आखिर तक निभाते रहे।



वे अंतिम सांस तक पार्टी गतिविधियों में शामिल रहे। वे ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन के जिला प्रधान रहे और ग्रामीण गरीबों को संगठित करने और उन्हें आंदोलनों में शामिल करने में स्मरणीय भूमिका निभाई थी। उनकी मृत्यु से पार्टी एवं जनआन्दोलन की हुई क्षति खलती रहेगी।

25 सितम्बर को जिला मुख्यालय पर रेवाड़ी की गोयल धर्मशाला में और 26 सितम्बर को गांव निमोट में हुई श्रद्धांजलि सभाओं में पार्टी नेता-कार्यकर्ता, अनेक गणमाण्य व्यक्ति, वकील, टीचर, सामाजिक कार्यकर्ता गांववासी, रिश्तेदार व परिवार वाले शामिल हुए। पार्टी के हरियाणा राज्य सचिव और डॉ. चंदन सिंह के बड़े बेटे कॉमरेड सत्यवान, जिला कमेटी की ओर से जिला सचिव डॉ. राजेन्द्र सिंह और लोकल कमेटी की ओर से डॉ. डॉ. रामकुमार ने पुष्पांजलि अर्पित की। कॉमरेड चंदन सिंह लाल सलाम!



रेवाड़ी : स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सत्यवान

एआईडीएसओ के उड़ीसा राज्य सचिव डॉ. शिवाशीष प्रहराज ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर छात्र आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए 52 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसमें डॉ. सुनील भोई को अध्यक्ष, डॉ. जगदीश मिश्रा व डॉ. कुशप्रुस्ती बाग को उपाध्यक्ष, डॉ. माधव महर को सचिव और लक्ष्मीधर सामल को कोषाध्यक्ष चुना गया।

गंजम : उड़ीसा के गंजम जिले की जिला कमेटी का दूसरा सम्मेलन 27 अगस्त को टाऊन हाल ब्रह्मपुर में हुआ। इसमें 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन से पहले ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से सम्मेलन स्थल तक शानदार जुलूस निकाला गया। सम्मेलन की अध्यक्षता एआईडीएसओ के राज्य सचिवमण्डल सदस्य डॉ. कार्तिक मोहंती ने की। मुख्य अतिथि के रूप में जाने-माने वकील श्री भगवान साहू ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। मुख्य वक्ता के रूप में सभा को एआईडीएसओ के उड़ीसा राज्य अध्यक्ष डॉ. अक्षय दास ने सम्बोधित किया। एआईडीएसओ के राज्य सचिवमण्डल सदस्य डॉ. सोमनाथ बेहरा ने भी विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा की। सम्मेलन में 61 सदस्यीय जिला कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष शिवानी शंकर मिश्रा, उपाध्यक्ष उद्धव महाकुद, सचिव निमाई चरण साहू और कोषाध्यक्ष नारायण साहू चुने गये।

महान नवम्बर क्रांति...

(पृष्ठ 6 का शेष)

उन्होंने आगे और कहा—“क्रांति शुरू होने पर जो क्रांतिकारी बन जाते हैं, वे सही मायने में क्रांतिकारी नहीं होते। जब प्रतिक्रियावादी ताकतें जबर्दस्त हमला बोलती हैं और जब उदारतावादी व जनवादी लोग सबसे अधिक दुविधा में रहते हैं, उस समय भी, जो क्रांति की विचारधारा और नारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं वे ही सही मायने में क्रांतिकारी होते हैं। सही क्रांतिकारी वे होते हैं, जो जनता को क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष करना सिखाते हैं और इस शिक्षा का नतीजा क्या होगा, शायद पहले से कोई नहीं बता सकता (अर्थात् भविष्यवाणी नहीं कर सकता)।” (वॉल्यूम-19 पेज-212)। “क्रांतिकारी आंदोलन में अगली लहर कब आयेगी ... कल, परसों या कई महीनों बाद—यह ऐसी कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिनका पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं होता।” (वॉल्यूम-8 पेज-139)। उन्होंने दिखाया,

“जन-क्रांति कब होगी, उसे तय नहीं किया जा सकता। ... जो लोग क्रांति की तैयारी कर रहे हैं, जनता पर यदि उनका प्रभाव रहे और अगर वे परिस्थिति का सटीक मूल्यांकन कर सकें, तभी क्रांति का समय तय किया जा सकता है।” (वॉल्यूम-8, पेज-153)।

इस प्रसंग में लेनिन की एक और सीख याद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, “आम तौर पर क्रांति के लिए ठोस परिस्थितियाँ क्या हैं? इस संबंध में नीचे जिक्र किये गये लक्षणों पर ध्यान देने से गलतियाँ नहीं होंगी: 1. जब शासक वर्ग के लिए बिना कोई परिवर्तन किये शासन-कार्य चलाना नामुमकिन हो जाता है, जब उच्च वर्ग के लोगों के अंदर किसी न किसी तरह का संकट पैदा हो जाता है, जब शासक वर्ग की नीति में संकट के चलते ऐसी दरार पैदा हो जाती है, जिससे शोषित-पीड़ित जनता के अंदर क्षोभ और नफरत के प्रगटीकरण का विस्फोट होता है। ‘दबे-कूचले लोग पुराने तरीके से और गुजर-बसर करना नहीं चाह रहे हैं’ ... यही लक्षण क्रांति के लिए पर्याप्त नहीं है। ‘उच्च वर्ग

के लोग भी पुराने तरीके से गुजर-बसर करने में असमर्थ हो रहे हैं’ ... इस परिस्थिति का पैदा होना भी क्रांति के लिए जरूरी है।

2. जब शोषित-पीड़ित जनता की दुःख-तकलीफों और मांगों की मात्रा में अन्य समय के मुकाबले काफी इजाफा हो जाता है।

3. उपरोक्त कारणों से जनता की सक्रियता काफी बढ़ जाती है। ‘शांत माहौल’ में जो जनता किसी विरोध के बिना खुद को लुटने देती है, वही जनता ‘बवन्दर के माहौल’ में वक्त के तकाजे के चलते और उच्च वर्ग की कारगुजारियों की वजह से सक्रिय हो जाती है और एक स्वतंत्र ऐतिहासिक भूमिका निभाती है।

वास्तविक स्थिति के इन सारे परिवर्तनों के बगैर आम तौर पर क्रांति का होना असम्भव है। इन सारे वस्तुगत परिवर्तनों के योगफल को ही क्रांतिकारी परिस्थिति कहा जाता है।” (वॉल्यूम-21, पेज-213)

(अगले अंक में जारी)

दिल्ली में शिक्षा सम्मेलन



दिल्ली : शिक्षा सम्मेलन को सम्बोधित करत हुए डॉ. ध्रुवज्योति मुखर्जी

28 सितम्बर को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की 109वीं जयंती पर नई दिल्ली में एवाने-गालिब सभागार में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 750 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉमरेड कमल साई ने की। विभिन्न विश्वविद्यालयों से जानी-मानी हस्तियों को मंच पर आमंत्रित किया गया और उन्होंने सभा को सम्बोधित किया।

वक्ताओं में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जियोलाजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. ध्रुवज्योति मुखर्जी, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली के पूर्व फेकल्टी मेम्बर प्रो. नरेन्द्र शर्मा, लेखक व बी. बरूआ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. दिनेश बैसया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन, दिल्ली के अध्यक्ष प्रो. अजय पटनायक, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन (डूटा) की अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ सेंटरल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन (फेडकूटा) की अध्यक्ष डॉ. नदिता नारायणन, एच.के. आर्ट्स कॉलेज,

अहमदाबाद के प्रो. हेमंतकुमार शाह और एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा शामिल थे।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो. एमरीटस प्रो. इरफान हबीब, जिवाजी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश के पूर्व वाइस चांसलर प्रो. पी.एस. बिसेन और कर्नाटक सरकार के पूर्व एडवोकेट जनरल प्रो. रविवर्माकुमार द्वारा भेजे गये सम्मेलन की सफलता के शुभकामना संदेश भी पढ़कर सुनाये गये।

बिरादराना प्रतिनिधि ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कॉमरेड पियूष मिश्रा और ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स ब्लॉक के महासचिव अमरेश कुमार ने भी सभा को सम्बोधित किया।

इस सम्मेलन के पैगाम को देश के कोने-कोने में फैला देने और शिक्षा, संस्कृति व मानवता पर हमले का प्रतिरोध करने के लिए जोरदार छात्र आन्दोलन गठित करने के संकल्प के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

सम्मानपूर्वक मनाई गई ईश्वरचंद्र विद्यासागर की 196वीं जयंती

मुम्बई (महाराष्ट्र) : ऑल इण्डिया सेव एज्यूकेशन कमेटी, महाराष्ट्र ने 25 सितम्बर को सेंटरल रेलवे हस्पताल, कल्याण के पास सेंटरल रेलवे इंस्टीच्यूट में सभा करके भारतीय नवजागरण काल के जाने-माने शिक्षाविद्, समाजसुधारक व आधुनिक शिक्षा के प्रणेता ईश्वरचंद्र विद्यासागर की 196वीं जयंती सम्मानपूर्वक मनाई। सभा की अध्यक्षता प्रो. दत्तू जी काजले ने की। मुख्य वक्ता श्री द्वारकानाथ रथ (सोशल साइंटिस्ट व कार्यकर्ता, गुजरात) के अलावा शिक्षा के व्यापारीकरण-विरोधी फोरम (एफएसीई), मुम्बई के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विवेक कोरडे, श्री भरत पवार और एआईडीएसओ की ओर से आकांक्षा त्यागी ने भी सभा को सम्बोधित किया।

सभा की शुरुआत सभापति व सभी वक्ताओं द्वारा ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। सभापति प्रो. दत्तू जी काजले के अध्यक्षीय भाषण व वाई.के. कुलश्रेष्ठ के द्वारा आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किये जाने के साथ ही सभा समाप्त हुई।



मुम्बई में सभा को सम्बोधित करते हुए द्वारकानाथ रथ

दिल्ली में सात वामपंथी पार्टियों द्वारा संयुक्त प्रदर्शन



दिल्ली : संयुक्त विरोध सभा को सम्बोधित करत हुए कॉमरेड रमेश शर्मा

दिल्ली में फैल रहे डेगू और चिकनगुनिया की रोकथाम में कोताही और इन बीमारियों से होने वाली मौतों पर केन्द्र व राज्य सरकार की आपराधिक उदासीनता के खिलाफ 26 सितम्बर को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय पर सात वामपंथी पार्टियों सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एमएल) एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), फारवर्ड ब्लाक, आरएसपी व सीजीपीआई द्वारा संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आये सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया।

सभी वाम दलों के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की ओर से राज्य कमेटी सदस्य कॉ. रमेश शर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि ऐसी बीमारियां जिनकी रोकथाम और इलाज आसानी से किया जा सकता है, उनसे देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में बीसियों लोगों का मर जाना राष्ट्रीय शर्म की बात है। करोड़ों रुपये स्वच्छता अभियान के विज्ञापनों पर खर्च किये जा रहे हैं

लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर लोग मर रहे हैं, उधर इलाज का बंदोबस्त करने की बजाय उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का खेल चल रहा है। कॉ. शर्मा ने लोगों से वामपंथी एकता को मजबूत करने और जीवन की ज्वलंत समस्याओं पर संयुक्त जनवादी आन्दोलन गठित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जनआन्दोलन ही बचने का एकमात्र रास्ता है। इसी रास्ते सरकार को अपनी जायज मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जा सकता है। एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड रितु कोशिक ने भी सभा को सम्बोधित किया।

सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने जिसमें एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य कॉ. हरीश त्यागी शामिल थे, उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की और मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। उपराज्यपाल ने उन मांगों पर तुरंत कदम उठाने का आश्वासन दिया।

1 नवम्बर, 2016 से 17 नवम्बर, 2016
महान नवम्बर क्रांति का शताब्दी वर्ष
सम्मानजनक ढंग से मनाएं

उद्योग समारोह

7 नवम्बर, 2016 प्रातः 11 बजे
मावलंकर सभागार, नई दिल्ली

अध्यक्षता : कॉमरेड रणजीत धर पोलित ब्यूरो सदस्य
मुख्य वक्ता : कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती पोलित ब्यूरो सदस्य

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट)